भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1572

उत्तर देने की तारीख – 09/12/2025

सरकारी भवनों में पहुंच की सुगमता में सुधार

1572. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दाहोद में सरकारी भवनों, बस अड्डों, अस्पतालों आदि की पहुंच की सुगमता में सुधार की स्थिति क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने दाहोद जैसे जनजातीय जिले में विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): चूंकि 'राज्य में निहित या राज्य के अधिकार क्षेत्र वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्य आईसीटी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए ज़िम्मेदार है कि विभिन्न योजनाएँ सुगम्यता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, ज़िला-वार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता हैं। पूरे भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए लागू दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) लागू करता है। इसमें एक घटक - "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण की योजना (सीबीईएफ योजना) है", जिसके माध्यम से मौजूदा सरकारी भवनों और कार्यालयों में अनुरूप प्रस्तावों की प्राप्ति के अनुसार माँग के आधार पर बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के तहत, विभाग को गुजरात राज्य सरकार से बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए अभी तक एक भी अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****